स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण योजना के कार्य निष्पादन की पुनरीक्षा

1767. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण योजना के कार्य-निष्पादन की पुनरीक्षा की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं कि स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवकों की प्रशिक्षण योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जायें। ।

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) जी हां।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राप्त उपलब्धिओं से पता चलता है कि प्रतिवर्ष औसतन लगभग 2 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 1991–92 में 3 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। इस मंत्रालय द्वारा जनवरी-दिसम्बर 1989 की अवधि के लिये आयोजित किए गए समवर्ती मूल्यांकन से यह देखा गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर नमूना आकार के लगभग 22 प्रतिशत ट्राईसेम लाभार्थियों को उसी कार्य के लिए आई० आर० डी० पी० की सहायता प्रदान की गई थी जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार (1991–92 के आंकड़ों के आधार पर) दर्जी का काम सर्वाधिक लोकप्रिय (लगभग 30 प्रतिशत) व्यवसाय है, जिसमें ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना (ट्राईसेम) के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है। अंबर चर्खा, रेशम कीट पालन, लौहारगीरी आदि भी कुछ अन्य लोकप्रिय व्यवसाय थे। कुछ राज्यों द्वारा इलेक्ट्रोनिक्स, आटोमोबाइल मरम्मत, हीरा तथा रत्नों की कटाई तथा पॉलिश करना आदि जैसे आधुनिक व्यवसायों को भी शुरू किया गया है जिसमें ट्राईसेम के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) ट्राईसेम कार्यक्रम में सुधार लाने हेतु किए गए उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना (ट्राइसेम) में सुधार लाने के लिए उठाये गए कदम

(1) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे ट्राईसेम के प्रशिक्षार्थियों के लिये रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों और रोजगार कार्यालयों के साथ बातचीत करें और उनके साथ समन्वय स्थापित करें। उत्पादन केन्द्रों के आस-पास की परियोजनाओं में रोजगार के अवसरों का सर्वेक्षण करके प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए कमद उठाए जा रहे हैं।

(2) परियोजना पर आधारित मजदूरी रोजगार शुरु करने को प्रोत्साहन दिया जाता है। इससे कुशलताओं में विविधता आएगी और इससे प्रशिक्षार्थियों को परियोजनाओं में खपाने के अवसर बढ़ेंगे।

(3) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को यह भी सलाह दी गई है कि वे ट्राईसेम के प्रशिक्षार्थियों में से उत्पादक ग्रुप बनाने, उत्पादन की ऐसी आधुनिक मदों, जिनकी मांग की कोई समस्या नहीं है, का निर्माण करने और विभिन्न प्रकार के पुर्जों को जोड़ने की संभाव्यता का पता लगायें। ऐसे उत्पादन ग्रुप विभिन्न प्रकार के पुर्जों को जोड़ने के काम तथा औद्योगिक इकाइयों द्वारा हस्तांतरित किए गए कार्यों जैसे घड़ियों के पुर्जे जोड़ना, कृत्रिम हीरा पॉलिश करना, आदि के लिए बनाए जा सकते हैं।

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा ट्राईसेम के लाभार्थियों के उत्पादों की प्रदर्शनियां आयोजित करना ताकि उनको वस्तुओं के विपणन हेतु बेहतर अवसर मिल सकें।

(5) ट्राईसेम कार्यक्रम के अन्तर्गत हीरे एवं रत्नों की कटाई तथा पॉलिश, घड़ियों के पुर्जे जोड़ना, टी० वी० सैट के पुर्जे जोड़ने और कम्प्यूटर उपयोग प्रशिक्षण जैसे आधुनिक कार्यों को शुरू किया गया है।

(6) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल करने के प्रतिशत को अब 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है और 3 प्रतिशत लाभ ट्राईसेम के तहत प्रशिक्षण हेतु शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिये निर्धारित किए जाने चाहिएं।

(7) ट्राईसेम के अन्तर्गत ग्राम स्तर पर ही छोटी-मोटी मरम्मत करने के लिए सामुदायिक कार्यकर्त्ताओं को हैंडपम्प मैकेनिकों के रूप में प्रशिक्षित करने का कार्य ट्राईसेम के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

Scheme for the Peasants living below the Poverty Line

1768. CHAUDHARY HARMOHAN SINGH : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) what is the number of peasants living below the poverty line in Uttar Pradesh;

(b) what are the details of the schemes launched so far by the Central Government, in order to ameliorate their living conditions; and

(c) what has been the extent of success achieved so far under the said schemes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) : (a) According to 43rd Round of National Sample Survey Organisation (1987-88) about 37.31 million people in the rural areas in U. P. were living below the poverty line. Majority of these people in the rural areas depend on agriculture or activities related to land. The state-wise number of peasants living below the poverty line is not available.

(b) and (c) To ameliorate the living conditions of the peasants and other weaker section in the rural areas, two major poverty alleviation programmes viz. Integrated Rural Development Programme (IRDP) and Jawahar Rozgar Yojana (JRY) are being implemented all over the country. Persons who are below the poverty line including peasants are recipients of the benefits under these programmes. IRDP is a self-employment programme in which both subsidy and credit are extended. Under JRY, supplementary wage employment is provided to the targeted population.

According to the Concurrent Evaluation of IRDP carried out during 1989, 39.28% of the beneficiaries had crossed the poverty line of Rs. 6,400/-.

Identification of problem villages in Maharashtra

1769. SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether Government have indentified the 'problem villages' in Maharashtra without supply of drinking water;

(b) if so, the number of such villages covered under the scheme to provide drinking water till the period ending September, 1992;

(c) the financial and technical assistance likely to be given to the State Government of Maharashtra in this regard; and

(d) the period by which all the problem villages are likely to be provided with clean drinking water ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) : (a) Yes, Sir.